के पोस्टरों में नारी देह का प्रदर्शन नहीं होगा, तो क्या स्कूटर नहीं बिकेंगे या कोई सौन्दर्य प्रसाधन नहीं बिकेगा। इसलिए यह जो नग्न प्रदर्शन किया जाता है, इस पर सरकार पाबन्दी लगाए। आज तक महिलाओं ने जो बाहर इसको रोकने के लिए प्रयत्न किये हैं और जो भावनाएं हैं, उन को देख कर सरकार को इस के बारे में कुछ सोचना चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट यह तो कर सकती है कि जो हमारा एडवरटाइजमेंट का इन्स्ट्रूमेंट है, टी० वी०, जिस पर बहुत से सोफ्ट ड्रिंक्स के एडवरटाइजमेंट्स होते हैं और नंगी फिल्में आती हैं, वे ऐसी होती हैं, जिन को हम देख भी नहीं सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि इस दिशा में आज तक जो प्रयत्न हुए हैं, वे कुछ छोटे दीखते हैं, नहीं तो उनका कुछ नतीजा जरूर निकला होता। तो मेरी यह प्रार्थना है कि इस विधेयक को सदन में सब का सहयोग मिले और इस के बारे में जितनी भी हमारी हिन्दुस्तान की महिलाओं की संस्थाएं हैं, उन के मेरे पास खत आए हैं और उन की भावनाओं को मैं यहां रखना चाहता हूं।

नारी के शरीर के खुले व्यापार के विषय में जितना भी कुछ कहा जाए; उतना ही कम है। हर एक उपयोग की वस्तुओं पर ऐसा भद्दा विज्ञापन छपता रहता है, जिस का जिक्र करना भी मुश्किल है और यहां पर दिखाने पर आप ने पाबन्दी लगा दी है।

I am placing this on the Table.

यह संस्कृति पाश्चात्य की हो सकती है, भारत की कभी नहीं और यह हमारे देश की संस्कृति नहीं हो सकती। पाश्चात्य संस्कृति में चाहे कैसा भी एडवरटाइजमेंट होता रहे। अगर हम इस पर पाबन्दी नहीं लगाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे नंगे फोटो छपते रहेंगे क्योंकि अब हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो एडवरटाइजमेंट्स में नारी-देह का प्रदर्शन किया जाता था, वह कम था लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इस को चाहे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और इस में कोई रुकावट नहीं है। यह जो नग्नता की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे शरीर को बिना कपड़ों के एड-वरटाइजमेंट में छापा जाएगा और हम देखते रहेंगे। हमारे भारत देश की जो पुरानी संस्कृति थी, उस संस्कृति को देखने के लिए बाहर के लोग यहां आते थे और हमारे यहां की संस्कृति को सीखने के लिए वे यहां आते थे। यह ऋषि-मुनियों का देश है। इसलिए इन चीजों पर कम से कम कुछ कन्ट्रोल तो किया जाए क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है, उस के मानस पर इस का खराब असर पड़ता है और इस के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हम अभी इस के बारे में नहीं सोचेंगे, तो यह सामाजिक बुराई कभी समाप्त नहीं होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr Patel, you can continue next time.

17.30 Hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
UNIFORM PRICES FOR FOODGRAINS

MR. DEPUTY SPEAKER : We shall now take up half-an-hour discussion. Shri H.N. Bahuguna.

श्री हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मौका दिया इस आधे घंटे की बहस के लिये। यह उस अतारांकित प्रश्न के सिलसिले में हो रही है जिसका उत्तर पहली अगस्त को इस सदन में दिया गया था। इस बहस को शुरू करते हुए पहली मेरी शिकायत यह है कि सवाल मेरा कुछ था और उसका जबाब कुछ आया। जो सवाल मैंने पूछा था उसका पहला हिस्सा यह था—

> "Wil the Minister of Food & Civil Supplies be pleased to state whether Government will consider uniform price for foodgrains throughout the country."

इन्होंने उसका जवाब दिया—

"Foodgrains are issued at a uniform price by the Government of India to all the States in the country."

मैंने पूछा था थ्रूआऊट द कन्ट्री, ये कहते हैं आल द स्टेट्स आफ द कन्ट्री। फिर मैंने दूसरा हिस्सा पूछा—

"on the lines of postal railways and petroleum products and as a first step to a beginning in the hills, which are at present discriminated against despite their weak economic conditions."

इस सवाल के पहले हिस्से का जवाब भी अलग और दूसरे हिस्से का जवाब क्या दिया—

"As the cost of transporting foodgrains in the hill States is high, Government of India is reimbursing the transport cost in those States upto the declared principal Distribution Centres."

मैंने पूछा था 'पहाड़ी क्षेत्र', इन्होंने उत्तर दिया 'पहाड़ी राज्य'। मैंने पूछा था 'सारा देश,' इन्होंने कहा कि 'सारे राज्य'। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे सवालों पर आपका सचिवालय ध्यान देता है कि हमारे सवाल ठीक हैं या नहीं, उसी तरह से हमारे सवाल के उत्तर ठीक हैं या नहीं, उनकी बाबत क्यों नहीं ध्यान देता। हमारे सवाल दिगर, जवाब दिगर। अगर इस तरह से होगा तो हमारी मर्यादा और इस सदन की मर्यादा रह नहीं पायेगी। पहला तो मेरा सबमीशन यह है।

दूसरे मेरा कहना यह है कि चलो आज उनकी हालत जो भी है, लेकिन इनका कहना जो यह है कि हम हिल्ली स्टेट्स के सारे इलाकों में ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सीडी देते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो 8 पहाड़ी जिले हैं जिनमें से गढ़वाल से प्रधान मंत्री जी को बहुत प्यार है और वे वहां अभी गई भी थीं, उत्तर प्रदेश में जो यह 8 जिले हैं जिनमें एक गढ़वाल की कांस्टीच्युएन्सी है और उसमें तीन जिले गढ़वाल, चमोली और देहरादून आते हैं, उसी में जो कुमायुं मण्डल है और गढ़वाल मण्डल है, इन दोनों जगहों पर जो जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है क्या वहां के लिए भी आप सब्सीडी दे रहे हैं? अगर आप पहाड़ी स्टेट्स को सब्सीडी दे रहे हैं तो जाहिर है कि पहाड़ी राज्यों से आपका मतलब सिक्कम, हिमाचल और कश्मीर से होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश के जो ये आठ पहाड़ी जिले हैं इनके लिए आप उस तरह से सब्सीडी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या आप यह सिखला रहे हैं कि आप अलग राज्य बना लो, हम आपको भी सब्सीडी देंगे? यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। आपको जो भी निर्णय लेना चाहिए वह बुनियादी आधार पर लेना चाहिए और उसे सब पर लागू करना चाहिए। जैसे आप ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में पहाड़ी राज्यों को सब्सीडी देते हैं, जो कि मेरी राय में बिल्कुल अपर्याप्त है, उसी तरह से आपको इन आठ जिलों के लिए भी सब्सीडी देनी चाहिए। वरना वहां के लोगों में दुर्भावना पैदा होगी और आपको कष्ट आयेगा। फिर आप मेरा नाम लगा देंगे कि तुमने गड़बड़ करा दी।

मान्यवर, एक बात यह है कि आई० एम० एफ० के कहने से फूड पर जब से सरकार ने सब्सीडी हटाई है तब से खाद्यान्नों के दाम बहुत बढ़ाये हैं। उसके लिए बहाना यह लिया है कि चूंकि हमने प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाई है इसलिए इश्यू प्राइस भी हम बढ़ा रहे हैं। अब चावल जो पहाड़ के लोग ज्यादा खाते हैं उसका दाम कितना बढ़ा। 1981 में 15 रुपए प्रति क्विंटल कामन वैरायटी, 20 रुपए प्रति क्विंटल फाइन वेरायटी, 10 रुपए प्रति क्विंटल सुपर फाइन वेरायटी। उसके बाद 1982 में 13 रुपए और बढ़ा दिए। जहां तक गेहूं का सवाल है उसके भाव भी 1981 में 15 रुपए, 1982 में 15 रुपए, 1983 में 12 रुपए बढ़ा दिए। इस तरह गेहूं पर इस सरकार ने 42 रुपए प्रति क्विंटल

बढ़ा दिए और चावल के दाम 33 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए। इस तरह से उस पहाड़ी क्षेत्र में मिलने वाले सामान की कीमत तो बढ़ा दी गई लेकिन सब्सीडी नहीं दी गई। यह सजा इन 8 जिलों को दी गई है। आम लोग कहते हैं कि यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोगों ने आपको चुन लिया है। यह बात ठीक नहीं है। जवाहर लाल नेहरू कहते थे—You should not only be good but you should be known to be good. I am afraid, this Government is not known, to be good.

यह बात ठीक नहीं है। जब आपने दाम बढ़ाए हैं और सब जगह आप सब्सीडी दे रहे हैं वहां पर भी सब्सिडी दी जाए।

बस्तर जिले की बात देखिए। मेरा सवाल बहुत व्यापक था। बस्तर जिले में फूड कारपोरेशन के गोदाम से जब गल्ला पिछड़े इलाकों में जाता है तो जितना वहां तक जाने का खर्चा होता है वह भी वहां के लोगों से लिया जाता है। इस तरह से उस आदिवासी को गल्ला महंगा मिलता है और पटना, इलाहाबाद, दिल्ली के रहने वाले को सस्ता मिलता है। यह तरीका गलत है। जो सरकार पूरे देश के लोगों को खाने की चीजें एक दाम पर न दे सके उसको लोकतांत्रिक और समाजवादी सरकार कैसे कहा जा सकता है। क्लेम यह है कि ये अपने आपको समाजवादी और लोकतांत्रिक कहते हैं। यह इनकी पहचान नहीं है।

तीसरा सवाल महंगाई का है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 1970-71 को अगर 100 मान लिया जाए तो यह 1982 में 231 हो गया और 1983 में 279 हो गया। प्राइस किस चीज की बढ़ी—चावल 13 परसेंट, ज्वार 9.6 परसेंट, बाजरा 17.4 परसेंट, मक्का 16.4 परसेंट, कोदो जो पहाड़ी लोग भी खाते हैं 14.8 परसेंट, मूंग 20 परसट, उड़द की दाल 22 परसेंट, आलू 53.5 परसेंट। आलू जो पहाड़ में सड़ गया। आलू टिहरी, चमोली में सड़ गया, बाहर नहीं निकल पाया। वहां पर कोई 30 रुपए क्विंटल तक खरीदने वाला नहीं था और जो आलू मैदान में होता है उसका भाव 53.5 प्रतिशत बढ़ गया। **This is the wholesale price indices of selected commodities during the last six months ending June, 1983.**

यह प्रश्न संख्या 42, 27 जुलाई 1983 के जवाब में मंत्री महोदय ने बतलाया है।

मेरा कहना है कि यह सरकार कैसी है। पहाड़ों में पैदा होने वाले आलू का दाम नहीं मिलता और उसको जो खाने के लिए सामान दिया जाता है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। आलू मैदान में आता है मैदान में पैदा होता है इसलिए 53 परसेंट बढ़ जाता है। जो आलू मैदान में पैदा होता है वह 53 परसेंट बढ़ जाता है। आपकी गवर्नमेंट इकोनोमी को कितना मिस-मैनेज कर रही है यह इससे सिद्ध हो जाता है।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एक बनी है। कंज्यूमर्ज के लिए वह क्या कर रही है, इसको भी आप देखें। आपकी फूड कारपोरेशन आफ इंडिया भी है जिसको आठ सौ करोड़ की सब्सीडी दी जाती है। 1983-84 के बजट में इस सब्सीडी की व्यवस्था की गई है। इस वास्ते यह इतनी बड़ी धनराशि रखी गई है ताकि जो चूहे खाएंगे, जो—ट्रांजिट लास होगा, जो खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी उसका पैसा उसको मिलना चाहिए। हमारे इस सदन के सदस्य सोचें कि फूड कारपोरेशन में जो वइंतजामी है उसके वास्ते आठ सौ करोड़ खर्च होने वाला है तो इस देश का क्या बनेगा।

प्रधान मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था। उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। यह पत्र 18 जुलाई 1983 को लिखा था। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैंने यही पत्र लिखा था। इसमें मैंने कहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग परिवहन का खर्चा अधिक होने के कारण सब से मंहगा अनाज खरीद रहे हैं। यह क्षेत्र रेल से दूर है। रेल से चार सौ किलोमीटर से लेकर आठ नौ सौ किलोमीटर दूर के—इलाकों की मैं चर्चा कर रहा हूं। वहां लदान का खर्च बहुत बढ़ गया

है। मैंने उन से मांग की थी कि इन क्षेत्रों में सरकार को परिवहन के खर्चे का एक हिस्सा सहायता के रूप में वहन करना चाहिये और इस प्रकार खाद्य सामग्री की कीमतों को घटाना चाहिये। इसके अतिरिक्त उचित कीमत की दुकानें केवल सड़क के किनारे स्थित हेलांग में ही नहीं होनी चाहिए। वहां से उरगम घाटी तक जाने के लिए सड़क नहीं है, घोड़े पर चढ़कर आदमी के लिए जाना आसान नहीं है, मुश्किल से दो तीन फीट चौड़ी सड़क है, जिस को पगडंडी कहते हैं और पैर पैर चलना पड़ता है। हेलांग से उरगम घाटी जाने के लिये पूरा एक दिन लगता है। हेलांग से ब्लाक है चमोली जिले में और वहां पहुंचने में तीन साढ़े तीन दिन लगते हैं और पैदल जाना पड़ता है। वान गांव है, मंडोली गांव है. वहां तक जाने में इतना समय लगता है। पीठ पर या घोड़े पर या बकरी पर घारचूल, गर्भयान पहुंचने में छः दिन में आदमी को लगते हैं और सिर्फ बकरी की पीठ पर ही सामान ले जा सकता है। सरकारी दूकान घारचूल में है। हम कहते हैं कि इस इलाके को भी आप देखें। यह सरहद का इलाका है। चीन के साथ इसकी सरहद लगती है। लाहोल स्पीति की भी यही हालत होगी। इस इलाके के लोगों की तो हालत यह है कि अगर आप वहां लोगों को जीवित रखना चाहते हैं तो जो चीनी हमें यहां खुले बाजार में पांच छः रुपये तक में मिल जाती है वही वहाँ चौदह रुपये में भी नहीं मिलती है और इसको आप को देखना चाहिये। गेहूं को हम यहां फेयर प्राइस शाप से लेते हैं और जिस भाव पर लेते हैं वही गेहूं वहां सौ परसेंट अधिक भाव पर दिया जाता है। फूड कारपोरेशन आपका कहां पर है। पहाड़ी जिलों में आपने फूड कारपोरेशन के गोडाउन वहां बनाए हैं? रेल हैड पर एफ० सी० आई० के गोडाउन बनाए हैं। ये अपने फिक्स किये हैं मैंने नहीं। वहां से, रेल हैड से माल की ढुलाई का खर्चा आप देखें। माना गांव जो आखिरी गांव है चीन के बोर्डर पर वहां जाएंगे तो ऋषिकेश से माना तक छः सौ किलोमीटर का फासला है। छः सौ किलोमीटर में ट्रक से ढुलाई का खर्चा माना का भोटिया भाई देगा जिस के पास खाने को नहीं है? वह तो छः महीने माना में रहता है और छः महीने बद्रीनाथ से भी ऊपर बर्फ में जब इलाका उसका दब जाता है तो नीचे आ जाता है, नदी के कीनारे किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, वह देगा? इस स्थिति में मेरा कहना यह है कि देश में खाद्यान्न वितरण का तरीका ठीक नहीं है। कुछ व्यवस्था भी आप करें लेकिन ऐसी करें कि देश के हर नागरिक को हर जगह पर एक रेट पर खाने की सामग्री मिल जाए। कम से कम यह तो करो। बिड़ला जी को भी चीनी वही भाव, मेरे को भी वही भाव और घर में झाड़ू लगाने वाले को, सड़क पर झाड़ू लगाने वाले को जो हमारा सफाई भाई हैं जिस के प्रति हम सब की सहानुभूति है, उसको भी चीनी वही भाव। आपने मिनिमम वेजिज तय कर रखी हैं। कहीं पर 150 कहीं पर 180 तक अलग अलग किस्म के लोगों के लिये। वक्त नहीं है बर्ना में पूरा इसके बारे में भी मैं कहता। उत्तर प्रदेश की सरकार को और खाद्य मंत्री को मैंने पत्र लिखा। मुख्य मंत्री को पत्र लिखा। गल्ला भी नहीं पहुंचा, बरसात शुरू हो गई, रास्ते टूट गये। फूड कार्पोरेशन के गोडाउन अगर जगह-जगह बन गये होते तो बरसात के पहले गल्ला सब जगह पहुंचा देते तो ठीक होता लेकिन इस इलाके में जब तक सड़कें नहीं हैं, वह सुविधा नहीं है जो रोडवेज की होनी चाहिये जिससे ट्रांसपोर्ट की कास्ट कम हो जायेगी। जब आप बड़े-बड़े शहरों में रेल हैड न होने की वजह से ट्रांस्पोर्ट का कास्ट नहीं लेते हैं, मिनिमम जितना ट्रांस्पोर्ट का कास्ट आप यहां लेते हैं वैसे ही लीजिये।

80 करोड़ रुपया आपका सफेद हाथी फूड कार्पोरेशन खा जाता है। इसमें 10 करोड़ भी सबसीडी होने वाली नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि यह सरकार दिल्ली से डरती है कि यह

कैपिटल ठीक रहे तो दूध यहां सस्ता है बजाय माना नाती के क्योंकि बाहर से जो मिल्क पाउडर आया है वह दूध में मिला दिया जायेगा । वह आया है मुफ्त में गरीबों के लिये । मेरा कहना यह है कि जो यह सारा धन्धा है, प्राइस पैटर्न, यह गरीब लोगों के लिये, पिछड़े इलाकों के लिये है । यह बात लागू होती है उड़ीसा, बोलनगीर, बस्तर, जैसलमेर के लिये । लाहौल स्पीत और दूरस्थ जो प्रदेश हैं, अरुणाचल का इलाका है उसके लिये । आप कितनी सबसीडी देते हैं और क्या भाव पड़ता है ?

अरुणाचल वालों का प्रतिनिधिमंडल यहां आया था । लीडर आफ अपोजिशन ने प्रधान मंत्री को प्रतिवेदन दिया है, हमको भी कापी दी है जिसमें कहा है कि हमारे यहां गल्ला सब जगह नहीं मिलता है । यह ट्रांपिग भी आप अपने कर्मचारियों के लिये करते हो, वहां के निवासियों के लिये नहीं करते हो । जब तक आप गल्ला सीमांचल के निवासियों को दें गे नहीं तो वह दुःखी होंगे और इससे देश का अहित होगा मैं समय रहते आपको कौशन करना चाहता हूं और आपका जो वचन आपके मैनिफैस्टो में लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए जो 20-सूत्री कार्यक्रम की इतनी बड़ी चर्चा है, माननीय व्यास जी इस सदन के सतर्क सदस्य हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह खुद देख लें और मैं उनके ऊपर न्याय छोड़ देता हूं । आप उनको फूड कार्पोरेशन का चेयरमैन बना दीजिये, सारे देश का मामला ठीक हो जायेगा ये बड़े न्यायप्रिय हैं । मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि सिसोदिया जी को हटा दीजिये, उनको भी रखिये, इनको भी बना दीजिये खासतौर से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिये इनको बना दीजिये तो यह सब ठीक कर दें गे क्योंकि न्यायप्रिय आदमी हैं ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है और भी लोग कहना चाहेंगे । मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा तो उन्होंने मुझे लिखा कि मैंने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इसमें जो मुद्दे उठाये हैं उनकी सफाई करो । मेरा कहना यह है कि ऐसा न हो कि सफाई यह हो जाये कि मुद्दे ही साफ हो जायें । मुद्दों का निर्णयात्मक हल निकालिये ।

पहाड़ी क्षेत्र के हर गांव में दुकान न खोलें । जैसे पटवारी रेवेन्यु लेने के लिये जाता है उसी तरह पटवारी को कहें कि २ महीने का राशन लेकर जाये और गांव वालों को बांट आये । कोई दुकान न रखें । जब तक ऐसा नहीं करेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों को दिल्ली की तरह राशन नहीं दें गे तो लोग भूखे मरेंगे । पहाड़ों में पैदावार 3 महीने की भी नहीं है साल भर में ।

इन शब्दों के साथ जो आपने मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों का ही नहीं, जो प्रश्न मैंने उठाया था, मैं अन्तिम प्रार्थना करता हूं कि मैं दोबारा उस प्रश्न को दूसरे रूप में उठाऊंगा मुझे सारे देश का उत्तर चाहिये । अगर आज आप उत्तर दे देंगे तो नहीं पूछूंगा कि सारे देश में एक भाव गल्ला बंटवायेगे या नहीं, साफ-साफ बतादें ताकि मामला साफ हो जाये कि सरकार का वर्ग चरित्र क्या है ?

MR DEPUTY-SPEAKER : I think your demand is quite reasonable.

SHRI H.N. BAHUGUNA ; I am grateful to you.

MR DEPUTY-SPEAKER : I do not know what the Government is going to say ; it is left to them. I feel it is reasonable. I do not impose my own views upon them. But I say I agree with you, especially in the case of hill stations.

SHRI H. N. BAHUGUNA : As far as I am concerned, I have won the game. I do not care whether the Government says "Yes" or "No". Daniel come to judgment.

श्री कमलनाथ झा (सहरसा) : आप तो केन्द्रीय मन्त्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सारे देश में एक दाम करने के लिये आपने क्या किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मेरे माननीय मित्र बहुत बड़े लोहायावादी सोशलिस्ट रहे हैं। पहले हम और ये अकेले में क्या बात करते थे मैं यहां बताना नहीं चाहता, अकेले मैं फिर कर लेंगे।

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) :

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Central Government supplies the foodgrains, namely, wheat and rice, to the entire length and breadth of the country at a uniform fixed price. There are several FCI godowns in the respective States and from those godowns the State Governments take them and add the distribution overheads, namely, the transportation charges, storage charges and administrative charges, sales tax and the margin money for the retailers. And the Central Government issues these foodgrains at Rs. 172 per quintal for wheat and Rs. 188 per quintal Common for rice. But, as you know, the Central Government is insisting on the State Government that the difference between the Central issue price and the retail price should not be more than Rs. 15 per quintal. But unfortunately some of the States do not follow this advice. It is varying from Rs. 6 to as much as Rs. 41 per quintal.

SHRI H. N. BAHUGUNA : Are you talking of the average or.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : Not average. Some States go up to as much as Rs. 41 whereas some States charge as little as Rs. 2, as in Andhra Pradesh.

Now, recounting the days Mr. Bahuguna ji was also an eminent Central leader and Uttar Pradesh Chief Minister, he was ruling the State during 1979-80. He gave the statistics of price rise. I would like to bring to his notice that in the 1979 drought situation the country was affected in respect of as much as 41 million hectares affecting a population of 24 crores and at that time when he was an important Central Minister, the inflation rose from 9.1 per cent in 1979 to 22.1 per cent in 1980, whereas if you look at this last years' drought, you will find that it affected 48 million hectares and a population of 31 crores, and it was declared that it was the worst drought ever seen in the entire century, and yet what is the inflation ? In 1982, it was 2.1 per cent, now it is 7.5 per cent. That clearly shows how competent we are compared to you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can also take some credit because he was also with you for some time.

(*Interruptions*)

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : Sir, as I told you, he is the one person who wants more power for the States, and at the same time he says, 'Now, you take away more', Now, what we are doing is, we are giving foodgrains at a fixed price at the respective FCI godowns in the States and we are giving them all the opportunities to see that this retail issue price is fixed as best as they can. For your information we are spending as much as Rs. 40.76 p. per quintal for wheat, which means Rs. 407.6 P. per tonne and Rs. 42.67 per quintal for rice which amounts to nearly Rs. 710 crores this year as subsidy to food prices. Should not the States spend a little more to see that at their respective places at every nook and corner the foodgrains reach at a reasonable price ? Lot of States, for example, in South – Karnataka, Andhra Pradesh and Tamilnadu, they are spending much more. They are giving rule to the people with very little margin, sometimes at price lower than the issue price. So, it is for the State Government. When Shri Bahuguna was the Chief Minister of Uttar Pradesh he should have seen that the price whether it was in Lucknow or Almora or Nanital had been the same, by seeing that the little transport cost were borne by the State Government.

Let me once again tell you, you need not compare the sugar price because in the sugar price, levy price is fixed at Rs. 3.75. That is because we have control over these mills. There are about 327 mills and we take as much as nearly 65% of it and we distribute throughout the length and breadth of the country at the priced price of Rs. 3.75 and no sales tax.

In foodgrains every State charges their own Sales Tax. How can we control ? We give guidelines. we request them We are incurring expenditure of Rs. 40/-per quintal on wheat and Rs. 42/-per quintal on rice, Kindly give little more subsidy so that the commodity reaches at a uniform point everywhere." I assure you we will make all efforts to see that the essential grains reach the common man.

SHRI H. N. BAHUGUNA ; The point is that they can change the Chief Minister of State from here. Uttar Pradesh Government is under them.

About Sales Tax I may state, when I was the Chief Minister I reduced at from 4% to 2%. Shri Narayan Dutt Tewari raised it from 3% to 4%. Transportation Cost 60% was borne by the State Government. at that time. But my successor reversed the whole cycle. Your physicians have created disease. You better cure them.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुगुणा साहब ने जो डिस्कशन चलाया है, जो चर्चा उठाई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सरकार जो तुरन्त घोषणा करने में कोई कठिनाई हो तो बाद में वह इस बात को अपने दिमाग में रखे। आज जो लोग गांवों में रहते हैं, जो आदिवासी हैं जंगलों में रहते हैं या जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है और यह बात बहुत गम्भीर है। जिस गांव माणा की वे चर्चा कर रहे थे वहां पर मैं डेढ़ महीने पहले गया था। उस समय मैं वहां गया था जबकि वहां बरफ हटाई जा रही थी। जिस आलू को उन्होंने नीचे डालकर रखा था, चार-छः महीने पहले, उसको वे लोग निकाल रहे थे। उसको देखने से मालूम होता था कि वे अपना जीवन किस तरह से बसर करते हैं। इसी तरह से मैं नागालैंड भी गया था वहां भी मैंने देखा कि लोग ढाई किलोमीटर आकर, अगर कहीं पानी जमा रहता है, तो उसको लेकर जाते हैं। इसी तरह से जो दक्षिणी बिहार है, जो छोटा नागपुर की कमिश्नरी है, जो संथाल परगना है वहां के सुदूर देहातों में आप जाइये तो आपको पता चलेगा कि उनका जीवन कितना कठिन है। उस दिन मन्त्री जी ने कहा कि वहां भी अन्न का भण्डार रहता है लेकिन खाली भण्डार रहने से क्या मतलब है ? अगर किसी के पास पर्चेजिंग कैपेसिटी नहीं है, खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं तो उसको आपके भण्डार से क्या मिलेगा ? यह जो बीच की दीवार है उसको कौन तोड़ेगा ? उसके पास पैसा कहां से आयेगा ? इस तरह जो जितने ही गरीब हैं उन पर उतनी ही अधिक मार पड़ रही है। नतीजा यह है कि आज जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको पता ही नहीं है कि यह देश आजाद है या गुलाम है।

18.00 Hrs.

उनके पास जो सामान पहुंचता है, वह कितने दामों में पहुंचता है, यह तो बाद की बात है, आज भी आप देहातों में चले जाइये, उनके अंगूठे के निशान लग जाते हैं लेकिन एक दाना चीनी भी उनको नसीब नहीं होती है। किसी पर्व या त्यौहार पर चावल और रोटी का सपना भी वे नहीं देख सकते हैं। आप कहते हैं कि इतने गोदामों में गल्ला रखा है, इतने एफ० सी० आई० के भण्डार भरे हैं। आप के रिजर्व बैंक स्टेट बैंक, जिन के मालिक पुजारी साहब हैं, से उनको क्या मतलब है। इसलिये सीधा सा प्रश्न है—आप गरीबों को सस्ते दर पर खाना दीजिये और जो जितना गरीब है उसके लिये सरकार को उतनी ही व्यवस्था करनी चाहिये।

आप अपने बार्डर के इलाकों में देखिये—नागालैंड, सारे का सारा पूर्वांचल, जो नौजवान वहां से निकल कर आयेगा, यदि उसमें थोड़ी सी भी अकल होगी तो वह महसूस करेगा कि हिन्दुस्तान मेरा है, लेकिन मेरे ही देश में मेरे साथ भेदभाव का व्यवहार हो रहा है। अभी हमारे यहां बिहार में झारखण्ड स्टेट की मांग चल रही है, कहीं गड़वाल स्टेट की मांग चल रही है। इनके पीछे केवल एक कारण है—

मेरे साथ जस्टिस नहीं किया जा रहा है। वह समझता है यदि मेरा अलग राज-पाट हो जायेगा तो हम को अधिक से अधिक शेअर सरकार में मिलेगा जिससे हमारा भी जीवनस्तर ऊंचा हो सकेगा। उसकी यह भावना जायज़ भावना है, लेकिन आप उस को भड़काने का काम न कीजिये। समय रहते हिन्दुस्तान के उन हरिजनों, आदिवासियों के लिये, जिन्होंने अभी तक आज़ादी को नहीं देखा है, उनके लिये आज़ादी को लाने का प्रयास कीजिये ताकि उनको भी यह अहसास हो सके कि वे भी इस आज़ाद देश के नागरिक हैं मैंने पहले भी कहा था—जब तक हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को अहसास नहीं होगा कि इस देश में जितने अधिकार महारानी को हैं, उतने ही अधिकार एक मेहतरानी को हैं, तब तक यह देश ऊपर उठ नहीं सकेगा।

बहुगुणा जी ने एक बहुत सीधा सवाल आप के सामने रखा है—इस देश में जो गरीब आदमी हैं आप चाहें उनको सस्ता न खिलायें लेकिन इतना तो करें कि जिस रेट पर वह दिल्ली में खाता है, लखनऊ में खाता है, पटना में खाता है, उसी रेट पर उस को भी दिलवाने की व्यवस्था कर दीजिये। यही सरकार का समाजवादी, बीस सूत्री काम होगा, आप कृपा कर इस एक सूत्री कार्यक्रम को पकड़ लीजिये, यदि आप इतना भी कर देंगे तो उसको अहसास होगा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, अन्यथा कीड़े-मकोड़ों के समान भर रहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri R.L.P. Verma.

Shri Bahuguna's speech is there and the Minister's reply is there. Therefore, you only put a pointed question. Everything has been very vividly described here. You only put a straight question. This is only a Half-An-our Discussion. Half an hour is already over. So, you must put only a question now.

(*Interruptions*)

SHRI SUDHIRGIRI : (Contai) Why are you intervening ? He has not yet started.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am only helping him.

SHRI SUDHIR GIRI : He knows everything. (*interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am only guiding him. Half an hour is already over. I can stop the Discussion now. Please sit down. You do not follow the rules. For everything you are getting up. Should I not guide him as to what he should do ? Let him put appointed question. It is between him and me. (*Interruptions*) you need not get up and interrupt. I know how to conduct the House. You cannot interfere like this. Don't record anything of what he says. (*Interruptions*)**

There is a limit to everything. I am only guiding him. Shri R.L.P. Verma.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष जी, बहुगुणा जी और श्री रामविलास जी ने जो कहा है, मैं उस से सहमत हूं लेकिन सादे देश में जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, उनके बारे में जो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया है, कि सारे हिन्दुस्तान में समान रेट पर चीजें दी जा रही हैं, वह मैं समझता हूं सही नहीं है। जिस तरह से पोस्ट-आफिसेज से, डाक-घरों से पोस्टल की सामग्री सारे देश में समान भाव से मिल जाती है और उसमें कोई विवाद नहीं होता है, उसी तरह से इस के लिए होना चाहिए। सरकार कहती है कि हर दुकान पर चाहे वह पहाड़ पर हो या मैदान में और चाहे वह गिरिजन हो या हरिजन हो, सब को चीजें बराबर दामों पर सरकार दे रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है और इसका कारण मैं यह समझता हूं कि आज देश में डाकघरों में सरकार कर्मचारियों को मन्थली वेतन देती है लेकिन वितरण प्रणाली वाली जितनी दुकानें हैं और करीब 2,856 दुकानें इस काम के लिए सारे देश में हैं, तो इन

**Not recorded.

दुकानों के जो मालिक हैं, उनको आप वेतन दे कर इस काम को नियोजित कीजिए ताकि उनको ब्लैक में इन चीजों को न बेचना पड़े ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चीनी की डुअल पालिसी के चलते जहां लैवी सुगर 3 रुपये 75 पैसे प्रति किलो मिलती है, वहां बाजार में वह 6.25 प्रति किलो मिलती है । यह जो बीच का अन्तर है, यह बड़ा प्रलोभन है और इसके लिए आफिसरों से मिल-जुल कर और सांठ-गांठ के द्वारा, यह जो बीच का दो-तीन रुपये का अन्तर है, उसमें वे उन से कुछ परसेन्टेज लेते हैं और इस तरह से उन लोगों को ब्लैक करने का अवसर देते हैं । इसलिए मेरा आप से यह कहना है कि ब्लैक को खत्म करने के लिए उन दुकानदारों का वेतन फिक्स करना चाहिए ताकि उन लोगों को आफिसरों को कुछ देना न पड़े और इस की ब्लैक वे न कर सकें । क्या आप इस तरह की कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग जो चीजों के दाम फिक्स करता है, तो गेहूं, धान और जो अन्य खाद्यान्न हैं, उन में किसानों की कितनी पूंजी लगती है, कितनी मजदूरी लगती है, कितनी बिजली की खपत होती है, कितना कीटनाशक दवाइयों पर उस का खर्च होता है और कितनी उसकी अपनी मेहनत लगती है, इन सब पर उस को कितना लाभ मिलना चाहिए, उसको ध्यान में रख कर दाम नहीं फिक्स किये जाते हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है । गेहूं के दाम आप ने 150 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स कर दिये जबकि यू0 पी0 गवर्नमेंट ने कहा कि 200 रु० प्रति क्विंटल फिक्स होने चाहिए और पंजाब ने कहा कि 175 रु०प्रति क्विंटल फिक्स कीजिए । अब तक अधिक दामों पर बाजार में गेहूं बिकता है और आप उसको कम दाम देते हैं, तो इसका नतीजा यह होता है कि इसमें भी ब्लैक होता है और दुकानों से माल ब्लैक में बाजार में जा कर बिकता है । इसके अलावा जो भारतीय खाद्य निगम है और जो राज्य के खाद्य निगम हैं, ये भी पर बैग परसेन्टेज लेते हैं इस कारण ब्लैक होता है । इस ब्लैक को रोकने के लिए आप को बाजार पर नियन्त्रण करना होगा । अगर बाजार में सामान सस्ता मिलेगा और जिस रेट पर आप दुकानों पर यह माल देते हैं, उस रेट पर बाजार में मिलेगा, तो फिर यह ब्लैक नहीं होगा और मैं तो यह समझता हूं कि यह जो सब्सीडी आप दे रहे हैं यह एक अपव्यय है और जनता का अरबों, करोड़ों रुपया बरवाद हो रहा है । तो मेरा यही कहना है कि इस चीज को आप को देखना चाहिए और आफिसरों के साथ मिलकर दुकानदार जो इन चीजों का ब्लैक करते हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या रहे हैं ।

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur) : If you cannot deliver the goods, at least allow me to tell something.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Central Government is giving at a uniform price, the State Governments are.....

SHRI H. N. BAHUGUNA : It is not correct. His reply is to incorrect. They are giving at the FCI godown at the uniform price and FCI godowns are located not in every part. I am talking of the consumer and it is essential. They have taken the responsibility or food distribution, food procurement and State Government is their agency. They must see that the State Governments fall in line. Otherwise, they can be dismissed like Mr. Jagannath Misra.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : We are not concerned whether the Central Government gives at a uniform rate or not. We are concerned with consumers and as far as the consumers are concerned, they do not get at a uniform rate.

हमें ऐसा लगता है कि इस देश में किसान ही सब से अधिक शोषित है आप उसके लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं । किसान को अपनी फसल के तुरन्त बाद ही अपना सारा गल्ला बेचना पड़ता है और बाद में सरकार से उसी गल्ले को सरकारी दुकानों के माध्यम से खरीदना पड़ता है । जिस मूल्य में उसे बेचना

पड़ता है और जिस मूल्य पर उसे खरीदना पड़ता है दोनों में अन्तर इतना अधिक होता है कि हम यह कह सकते हैं कि किसान आज बहुत शोषित है।

लेकिन लोग कहेंगे कि शोषित तो और लोग भी हैं। आप जरा इसको गंभीरता पूर्वक देखिये कि मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिये संगठित हो कर हड़ताल कर सकता है, सरकारी कर्मचारी भी संगठित हो कर हड़ताल कर सकते हैं। आजकल तो सरकारी अफसर भी संगठित हो कर हड़ताल करने की धमकी दे सकते हैं। इन वर्गों के लोग अपने परिवारों के साथ इस देश की जनसंख्या का एक चौथाई भाग हैं। इस एक-चौथाई भाग पर इस देश का अधिक खर्च होता है, उनका वेतन बढ़ता है, मंहगाई भत्ता बढ़ता है। तो यह सारा खर्च उन पर चला जाता है। जो देश की जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग है जिसमें कि अधिकतर किसान हैं, वह सब से अधिक शोषित हैं। उसको लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए ताकि वह अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके, अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा कर सके। इसके साथ-साथ उसे अपना स्टेण्डर्ड भी मेन्टेन करना है इसलिए उसे लाभ कारी मूल्य मिलना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है।

अब मैं तीन-चार प्रश्न करना चाहता हूं।

(1) क्या कृषिजन्य कच्चे माल और कारखाने के उपभोग्य माल के मूल्यों के बीच में कोई अनुपात निर्धारित करेंगे ?

(2) क्या खाद्यान्नों के मूल उत्पादक किसान को दिया जाने वाला लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं से लिया जाने वाले मूल्य का स्थिर अन्तर 20 प्रतिशत निर्धारित करेंगे ?

(3) अपेक्षाकृत पिछड़े इलाके में रेलवे लाइन और सड़कों का अभाव है। ऐसे क्षेत्र में सड़क से ढोये जाने वाले खाद्यान्नों में यातायात खर्च में सरकार अनुदान देगी ?

जो देश के पिछड़े क्षेत्र हैं वहां यातायात की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहां जाने के लिये कच्ची सड़कें हैं। इसके कारण दूरदराज के इलाकों में खाद्यान्न का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। अगर ईमानदारी से कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न बेचता है तो उस दुकानदार को लाभ नहीं रह सकता है, वह हमेशा घाटे में रहेगा। वह अपने घाटे को पूरा करने के लिये काला धन्धा करता है। एक दफा जब वह काला धंधा शुरू कर देता है तो उसको करने की उसको आदत पड़ जाता है और फिर वह हमेशा ही काला धंधा करता है। इस चीज को रोकने के लिए मैंने ये प्रश्न किये हैं। क्या सरकार सारे देश के देहातों में एक यूनीफार्म प्राइस पर चीजें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी और वहां पर चीजें पहुंचाने के लिए सब्सीडी देगी ?

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : मेरी केवल यह मांग नहीं है कि केवल चावल और गेहूं जो केन्द्र सरकार पूरे देशों में बांटती है वही यूनिफार्म प्राइस पर मिले, बल्कि जितनी भी खाद्य सामग्री है वह पूरे देश में खासतौर कमजोर वर्ग के लोगों को यूनिफार्म प्राइस पर मिले। इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? यह बात अलग है कि जो चीज राज्य सरकार के नियंत्रण में है उस पर सीधा नियंत्रण केन्द्र सरकार नहीं रख सकती, लेकिन क्या उन राज्य सरकारों को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वे इस दिशा में काम करें ? जब राज्य सरकारों को डिसमिस करना होता है तो म्युनिसपेलिटी की तरह कर दिया जाता है। क्या इस बारे में उनसे बात नहीं की जा सकती ? इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? इसके साथ ही सरकारी दूकानों पर जिस भाव पर सामान मिलता है, उसी भाव पर बाजार में भी सामान मिले, इसके लिए क्या कदम उठाएगी ?

हर ब्लाक में फूड कारपोरेशन अपना गोदाम खोले । खासतौर से पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में और देश के सुदूर स्थानों में हर ब्लाक में फूड कारपोरेशन का गोदाम होना चाहिए ।

I want to know whether you are going to set up Food Corporation Godowns in every block and especially in those areas which are situated on the borders and in the hilly regions.

क्या आप राज्य सरकारों को यह निर्देश देंगे या राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर उनसे आग्रह करेंगे कि ब्लाक लेवल पर फूड कारपोरेशन का गोदाम हो और उस गोदाम से सरकारी कर्मचारी, जैसे ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, ए डी ओ, ग्राम सेवक, पटवारी आदि खाद्य सामग्री ले जाकर गांवों में वितरित करें । इससे बिचौलियों के बीच में आ जाने से जो समस्याएं आ जाती हैं, वे काफी हद तक समाप्त होंगी । इस तरह के क्या सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देगी ?

जब सूखा पड़ता है या शीतलहार होती है तो उस समय भूखमरी फैलती है । उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तमाम लोग शीतलहर में भुखमरी से मरे थे । यहां से पहले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी विधायक थे । इसके अलावा बिहार, राजस्थान में अक्सर सूखे के कारण भुखमरी के समाचार पढ़ने को मिलते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सूखा या शीतलहर होती है उस समय में भुखमरी की स्थिति में कीमतें भी तेजी के साथ बढ़ती है, उन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ताकि कमजोर लोगों को सस्ते दाम पर खाद्य सामग्री आसानी से मिल सके ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister.

SHRI H. N. BAHUGUNA : In one sentence you can finish the whole thing—that you will try to give at the uniform rate.

SHRI M. S. SANJEEVI RAO : Mr. Paswan has raised the issue whether we will be able to give at a reasonable price particularly to the backward areas and also to hilly areas.

I would like to inform this august House that particularly for the 9 hill States like Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim, knowing that these 9 States are hilly States and there is very little transportation, particularly, rail transportation, we have taken steps to see that the transportation charges from the FCI godowns to their principal cities are subsidised. ...

SHRI H. N. BAHUGUNA : Subsidised means what ?

SHRI M. S. SANJEEVI RAO : The common man in these 9 hill states gets at very reasonable price the foodgrains, whether it is rice or....

SHRI H. N. BAHUGUNA : Question.

SHRI M. S. SANJEEVI RAO : This is again the same thing which Mr. Bahuguna wanted for the Hill State of U.P.

SHRI H. N. BAHUGUNA : Do you want the hill districts of U.P. to be States before they can get back the benefits ? And is it your suggestion ? I am merely acting on your advice and I may tell them accordingly.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : I am saying that hill districts are not only located in U.P. but they are also located in Rajasthan and Madhya Pradesh. A state like U.P., with all its resources should also look after the ten per cent of the hill population, particularly, in view of the fact that the Central Government is spending such a huge amount of Rs. 710 crorer. That is what I said.

SHRI H. N. BAHUGUNA : What about the price ?

SHIR M. S. SANJEEVI RAO : Now, Sir, coming back to Mr. Paswan.

He was telling that the people living below the povertyline should get the priority in the matter of the supply of a commodity

at a reasonable price. This is the very reason why in our 20-Point Programme, under the 15th Point, we have made it a point that they get the commodity at a reasonable price.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : You may be spending crores of rupees. But, what is the ultimate achievement ?

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : That was the reason why I say this. In 1980 we had only 2,52,000 fair price shops. Now, we have nearly 2,90,000 fair price shops spread all over India. Our aim is that we should have a fairprice shop for every 2,000 people. Also, we want these fairprice shops more and more for the tribals as also the harijan people

With this background, we are working. Let me tell you, as I told you earlier, in spite of the drought year we had, realising the situation, we sent as much as 10.87 million tonnes of grains this year in these eight months, compared to 9.67 lakh tonnes sent last year. This is the step we have taken.

Shri Harikesh Bahadur raised the question about edible oil supply. We used to give only 30,000 tonnes upto May but in June and July, particularly, in addition to 47,000 tonnes, we have raised this to 60,000 tonnes, that is, we have supplied 13,000 more tonnes. This was the distribution made to the States. This was nearly 20% more. Above all this, what we have done is this. We used to give Vanaspati to the extent of 60% of the requirements. Now, because of the drought situation, we have given 20% more so that vanaspati can be easily available through the year. This is the step we are taking. We are ready to take a number of steps. I do not know why Mr. Bahuguna was repeatedly talking about the dismissal of Dr. Jagannath. Is he recollecting the past about his own dismissal ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : I am trying to simply say this. Are we discussing the price or about the supply of grains ? About the price he is running away, Sir.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : I am not running away. You are running away.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You deal with Mr. Verma's point. You may go one by one.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : As regards Mr. Verma's point, I have told him repeatedly that our emphasis is more on the public distribution system. We are all the time seeing that fair price shops are given to the respective States.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He wants that the public distribution system should be extended to the village level and to hill areas.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : That was what I was repeatedly telling. The Centre is giving foodgrains through the State Governments. Let me tell you that State Governments are not controlled only by Congress (I). There are several States run by different parties. Do not forget about it. What I am telling is that you are particularly insisting on more autonomy for the States. We are giving the grains to the respective States at a fixed price. That is how the grains are distributed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now you come back to Prof. Mehta.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : Mr. Mehta has told us about the sufferings of the farmers. I totally agree with him. That is the very reason why we are increasing the support price regularly, for which Mr. Bahuguna is repeatedly saying why we are increasing the price of rice and all that regularly. How can we do that unless we do that.

SHRI H.N. BAHUGUNA : We protest. The hon. Minister should do his homework. From the support price and the issue price you are making profit.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : Out of that we are giving 40% subsidy for wheat and 42% for rice.

SHRI H.N. BAHUGUNA : Earlier it was much more.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : Shri Harikesh Bahadur said there should be godown in every block. I want him as he claims as if he is a big technocrat of Uttar

Pradesh from the Banaras Hindu University, to let us know will it be viable to have a big FCI godown in every block ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : Yes.

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : We give it to the State and it is for the State to build their own warehousing corporation and supply it.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Why did I make this suggestion, because this transport charge will be on the Government and the people will not have to pay for the transport. That is why we want.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister has answered all the main questions. Half-an-hour discussion is over.

18.27 Hrs.

EMIGRATION BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are amendments to the consideration Motion. We will dispose of them.

I will now put Amendment No. 2 moved by Shri R.L.P. Verma to the vote of the House.

Amendment No. 2 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put Amendment No. 3 by Shri E. Balanandan to the vote of the House.

Amendment No. 3 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put Amendment No. 4 and 5 by Shri G.M. Banatwala to the vote of the House.

Amendment Nos. 4 and 5 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put Amendment No. 39 by Shri M.M. Lawrence to the vote of the House.

Amendment No. 39 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the Question is :

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to emigration of citizens of India, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up Clause-by-clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Clause 2 Shri G.M. Banatwalla is not present and Shri Mool Chand Daga is not moving his Amendment.

The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill.

The Motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER ; Now clause 3. Shri R.L.P. Verma is absent.

The question is :

"That Clause 3/stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : CLAUSES 4 AND 5—Shri G.M. Banatwalla and Shri R.L.P. Verma are absent. And in Clause 5 there is no Amendment. So, I will put both the Clause together to the vote of the House.

The Question is :

"That Clauses 4 and 5 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

CLAUSE 6—EMIGRATION CHECK-POSTS

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri G.M. Banatwalla and Shri R. L. P. Verma are absent. Shri Mool Chand Daga, are you moving your Amendment ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : I am moving my amendment.

I beg to move :

Page 4, line 32,—

for "specified" *substitute* "notified" (43)

It is a very valid amendment. It should be accepted. Why should it be specified ?